सत्यमेव जयते

गनतंत्र दिवस सम्बोधन

प्रो. जगदीश मुखी

मानननीय राज्यपाल, असम

गुवाहाटी २६ जनवरी २०२०

गणतंत्र दिवस के अवसर पर
माननीय राज्यपाल का भाषण

मेरे प्रिय असमवासियों,

आज, हमारे राष्ट्र के इकहत्तरवें गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर, मैं असम सहित पूरे देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएँ प्रदान करता हूँ।

राष्ट्र हमें एक सूत्र में बांधता है। राष्ट्र से संबंधित प्रतीकों का विशेष महत्व होता है। इसलिए राष्ट्रध्वज सिर्फ कपड़े का टुकड़ा नहीं हमारा स्वाभिमान है। राष्ट्रगान सिर्फ शब्द नहीं, हमारा आत्म-सम्मान है। वैसे ही संविधान सिर्फ एक किताब नहीं हमारी प्राणशक्ति है। हम संविधान के प्रति निष्ठा रखते हुए, सरकार के रूप में, नागरिक के रूप में अपने-अपने कर्तव्य का पालन करते रहें, यही संविधान के प्रति सच्चा सम्मान होगा।

आज देश का हर नागरिक हर्ष और उल्लास के साथ गणतंत्र दिवस मना रहा है। आइए, इस शुभ अवसर पर हम अपने संविधान निर्माताओं के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करें, जिनके ज्ञान, अनुभव और दूरदृष्टि के कारण हम ऐसी व्यवस्था का निर्माण कर पाये हैं, जिसमें बिना भेदभाव के, बिना भय या पक्षपात के, देश का हर नागरिक अपनी स्वतंत्र सत्ता को अनुभव करता है, अपनी आशा और आकांक्षाओं को पूरा करने का यत्न करता है।

इस शुभ दिन, हम आजादी के उन दीवानों का भी स्मरण करें, उन्हें अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि दें, जिनके अथक प्रयासों और बलिदानों से हमें हमारी स्वतंत्रता मिली। आज वह अवसर है, जब हम फिर एक बार अपनी स्वतंत्रता, अपनी व्यवस्था, अपने संविधान का मूल्य जाने, उसके महत्व को स्वीकारें और अपनी समस्त शक्तियाँ देश को और सशक्त, और समृद्ध करने में झोंक दें।

संस्कृति हमें निरंतरता, पहचान और स्थायित्व देती है। यह हमारा सौभाग्य है कि हमने इस देश में जन्म लिया;

जिसने कल्पना, चिंतन, दर्शन, विज्ञान, कला और अध्यात्म की हर ऊँचाई को छुआ, जिसने विश्व-बंधुत्व और मानव-कल्याण का संदेश दिया।

पूरी दुनिया आज हमें आशा भरी दृष्टि से देख रही है। भारत अपार संभावनाओं का देश है। हमें अपनी सभी संभावनाओं को तलाशना होगा, उन्हें सच करना होगा। एक ऐसे भारत का निर्माण करना होगा, जिसमें भूख, गरीबी, बेरोज़गारी न हो, जो सशक्त हो, समृद्ध हो और जो विश्व को राह दिखाये। सदियों से भारत ने अपने ज्ञान और अध्यात्म से विश्व का मार्गदर्शन किया है। और अब अपने विज्ञान, अर्थ और कौशल से भी करेगा। आज देश तेजी से आगे बढ़ रहा है।

राज्य सरकार असम के मूल निवासियों के अधिकारों के प्रति पूरी तरह समर्पित है। इसलिए हम पिछले साढ़े तीन वर्षों से बराक, ब्रह्मपुत्र, पहाड़ और घाटी में समन्वय बनाते हुए, असमीया अस्मिता के प्रति पूरी निष्ठा रखते हुए काम कर रहे हैं। असम समझौते की धारा-6 के पूर्ण क्रियान्वयन पर ज़ोर देना, इसी नीयत और नीति को रेखांकित करता है। गौहाटी

उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश, जस्टिस बिल्लव शर्मा की अध्यक्षता में केंद्रीय सरकार ने एक उच्चस्तरीय समिति का गठन किया था। इस समिति में समाज के अति सम्मानित और विद्वान व्यक्ति हैं, जिनके ज्ञान, अनुभव का लाभ असम को मिलेगा और समिति अपनी रिपोर्ट अति शीघ्र केंद्र सरकार को सौंप देगी, जिसके बाद असम के लोगों को संवैधानिक सुरक्षा कवच मिलेगा और उनके राजनीतिक, सांस्कृतिक और भाषाई अधिकार हमेशा के लिए सुरक्षित हो जाएँगे। यह हमारा विश्वास है कि केंद्र और राज्य सरकार मिलकर असम को एक नया विश्वास देंगे, उसकी विकास की गति को तेज़ और तेज़ करेंगे। राज्य सरकार ने कुछ ऐसे कदम उठाये हैं जिनसे हमारी प्रतिबद्धता साफ दिखाई देती है। संविधान में संशोधन कर असमीया को राज्य भाषा के रूप में मान्यता दिलाने के लिए कैबिनेट ने एक प्रस्ताव ग्रहण किया है, जिसके तहत हमने केंद्र सरकार से इस दिशा में आवश्यक कदम उठाने के लिए अनुरोध किया है। साथ ही **भाषा गौरव** नाम की योजना शुरू की गयी है, जिसमें असमीया में लेखन करने वाले नये लेखकों को आर्थिक सहायता का प्रावधान है।

गैर सरकारी विद्यालयों में असमीया भाषा को पढ़ाया जाना अनिवार्य किया जाएगा। इसके लिए अति शीघ्र आवश्यक कानून बनाया जाएगा। असम साहित्य सभा को 10 करोड़ की धनराशि, बोड़ो साहित्य सभा को 5 करोड़ की धनराशि और अन्य बीस साहित्य सभाओं को 3 करोड़ प्रति सभा के हिसाब से अनुदान देने का निर्णय लिया गया है। सरकार सभी साहित्य सभाओं को मज़बूती प्रदान कर रही है, ताकि वे भाषा के प्रचार-प्रसार का काम प्रभावी ढंग से कर सकें।

जाति, माटी और भेटी हमारे लिए सिर्फ नारा नहीं, संकल्प है। और यह संकल्प अटल है। इसे पूरी प्रामाणिकता के साथ हम अपने कार्यों और निर्णयों में उतार रहे हैं। इसी ध्येय के साथ हमने नयी भूमि नीति बनायी, जिससे मूल निवासियों की भूमि को सुरक्षित रखा जा सके। भूमिहीन परिवारों को भूमि पट्टा देने का काम शुरू कर दिया है और जल्द ही हम 1 लाख भूमिहीन लोगों को ज़मीन के पट्टे देने के काम को पूरा कर लेंगे।

हमारे सत्र हमारी अस्मिता के प्रतीक हैं। वे हमारे धर्म, संस्कृति और आध्यात्मिक विरासत के प्राणकेंद्र हैं। इसलिए

उनके संरक्षण के लिए सरकार ने विशेष कदम उठाये हैं। सत्र की भूमि पर किसी भी तरह के अतिक्रमण को हटाना हमारा परम कर्तव्य है और हम लगातार इस दिशा में आवश्यक कार्यवाही कर रहे हैं। 160 सत्र और धार्मिक संस्थानों को **असम दर्शन** योजना के तहत 2 लाख प्रति संस्थान की सहायता भी दी जा रही है।

असम में सदियों से विभिन्न भाषा, पंथ और मूल के लोग एक साथ मिलकर रह रहे हैं। असम की मिट्टी, उसकी संस्कृति और सभ्यता में सबकी चमक और खुशबू है। हमें अपनी एकता बनाये रखनी है। साथ ही समाज के जिन वर्गों को विशेष सुरक्षा और संसाधनों की आवश्यकता है उनके लिए सरकार विशेष कदम उठा रही है। हमने मोरान, मटक और कोच राजवंशी समुदाय के लिए नयी स्वायत्तशासी परिषद और ताई आहोम और सुतिया समाज के लिए विकास परिषद के पुनर्गठन का फैसला लिया है। सती साधनी की जन्म जयंती पर राजकीय अवकाश की घोषणा और गोलाघाट में सती साधनी राज्यिक विश्वविद्यालय की स्थापना का निर्णय समाज की आशा और आकांक्षा को पूरा करने में उठाये गये हमारे कदम हैं। इसके

साथ ही मोरान, मटक, सुतिया और आहोम समाज के लिए क्रीड़ा, कौशल विकास और रोज़गार सृजन के क्षेत्र में नयी योजनों के लिए 125 करोड़ रूपये प्रति समाज की दर से विशेष पैकेज की घोषणा की गयी है। सराईदेव को **वर्ल्ड हेरिटिज साइट** के तौर पर मान्यता दिलाने के लिए भी जरूरी कदम उठाये जा रहे हैं।

चाय जनजाति के हमारे भाइयों-बहनों के लिए भी हमने कई कदम उठाये हैं। उन्हें जमीन के पट्टे देने के साथ जनजाति के विद्यार्थियों को दस हजार रुपयों की **सेमों सिंह होरो** विशेष छात्रवृत्ति, रोज़गार-सृजन के लिए दयाल दास पनिका स्वनियोजन आसोनी, अन्न योजना के तहत 2 किलो चीनी प्रति परिवार देना और बागानों में 100 नये हाई स्कूलों की स्थापना शामिल हैं।

असम समझौते को सही अर्थों में लागू किया जा रहा है। भारत-बांग्लादेश सीमा को पूरी तरह सील करने की दिशा में कारगर कदम उठाये गये हैं और जो थोड़ा हिस्सा अभी बाकी है वो भी सील कर दिया जाएगा, जिससे अवैध अनुप्रवेश पर

स्थायी रोक लगेगी। असम आंदोलन के शहीदों के प्रति सम्मान और कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए सरकार ने 804 शहीदों के परिवारों को 5 लाख प्रति परिवार के हिसाब से आर्थिक सहायता प्रदान की है। साथ ही उन व्यक्तियों को जो आंदोलन में गोली से चोटिल हुए थे, उन्हें 2 लाख प्रति व्यक्ति की आर्थिक सहायता प्रदान की गयी है। शहीदों के प्रति सम्मान के प्रतीक स्वरूप, शहीद स्मारक पार्क की आधारशिला भी 10 दिसंबर, 2019 को रखी गयी। गुवाहाटी शहर के पश्चिम बोरागांव में बनने वाला यह स्मारक वर्तमान और भविष्य को उन शहीदों के अमर बलिदान का स्मरण कराता रहेगा।

यह सरकार समाज के हर वर्ग के लिए है, और उन वर्गों के प्रति विशेष रूप से समर्पित है, जिन्हें विकास और सुरक्षा की अधिक आवश्यकता है। इसी को ध्यान में रखते हुए हम काम करते आ रहे हैं। हाल में ही राज्य सरकार ने कई महत्वपूर्ण निर्णय लिये हैं जिनमें से कुछ का उल्लेख मैं आज अवश्य करना चाहूंगा। इन निर्णयों के पीछे की भावना और समर्पण को समझना आवश्यक है। क्रीड़ा और संस्कृति जगत से जुड़े 2,000 समर्पित व्यक्तियों को 50,000 रुपये प्रति व्यक्ति के हिसाब से

एकमुश्त सहायता देने का फैसला लिया गया है। असम के सिनेमा के समुचित उन्नयन के लिए एक नयी फिल्म पॉलिसी बनायी गयी है। हमारी सरकार पंचग्राम और नगाँव पेपर मिलों के कर्मचारियों के प्रति संवेदनशील है। उनकी परेशानी को आंशिक रूप से ही सही, कम करने के लिए, विशेषकर उनके बच्चों की पढ़ाई सुचारू रूप से चलती रहे, इसके लिए एककालीन आर्थिक सहायता देने का फैसला लिया गया है।

विगत कई वर्षों से, या यूँ कहूँ कि दशकों से, असम की छह जनगोष्ठियाँ मोरान, मटक, सुतिया, कोच राजवंशी, ताई आहोम, चाय जनजाति इस बात के लिए संघर्ष कर रही थी कि उन्हें अनुसूचित जनजाति की मान्यता दी जाए। हमने उनकी बात को समझा, उनकी पीड़ा को, उनके सपनों को समझा। इसलिए केंद्र सरकार ने यह फैसला किया है कि इन सभी छह जनगोष्ठियों को अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिया जाएगा। ऐसा करते हुए हम इस बात के लिए भी सचेत हैं कि मौजूदा अनुसूचित जनजातियों पर किसी तरह का दबाव या प्रभाव न पड़े। हम असम के समग्र विकास के लिए कटिबद्ध हैं और साथ ही यहाँ के हर वर्ग की आशा और आकांक्षा को पूरा करने के

लिए भी पूरी तरह समर्पित हैं। इसके लिए राज्य सरकार ने मंत्रियों के एक समूह का गठन किया है, जो सभी पहलुओं पर विचार करने के बाद एक प्रतिवेदन सौंपेंगे जिसके आधार पर केंद्रीय सरकार इस दिशा में ठोस कदम उठाएगी। यह असम की अस्मिता को सुरक्षित रखने के प्रति हमारी प्रतिबद्धता दर्शाता है।

इस सरकार की नीयत साफ है, नीति स्पष्ट है। हम राज्य के विकास के लिए पूरी ईमानदारी से काम कर रहे हैं। विकास तेज़ गति से हो, समाज के शोषित, वंचित वर्ग को इसका विशेष लाभ मिले, यह हमारा ध्येय है। विगत साढ़े तीन वर्षों में छह हज़ार किलोमीटर से अधिक रास्तों का निर्माण, बुनियादी ढांचे में निवेश, गुवाहाटी में नये एयरपोर्ट का निर्माण, बोगीबिल पुल का पूरा होना, एम्स का निर्माण कार्य, नये मेडिकल और इंजीनियरिंग महाविद्यालयों का निर्माण, इंद्रधनुष गैस ग्रिड का निर्माण, ये सभी राज्य के समग्र विकास के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं।

सरकार आम आदमी के जीवन को कैसे बेहतर बनाये, इस संकल्प से हमारा हर काम, हर कदम संचालित होता है। यही कारण है कि आज राज्य में 92 प्रतिशत जनता स्वास्थ्य सुरक्षा के दायरे में हैं, 99 प्रतिशत घरों में शौचालय हैं, 99 प्रतिशत घरों में बिजली हैं, 27 लाख किसानों के खातों में सीधे 1,598 करोड़ रुपये जमा कराये गये हैं, 1 करोड़ 45 लाख जन धन योजना के खाते खोले गये हैं, तीन लाख नये आवास, 10 लाख युवाओं को मुद्रा लोन इत्यादि दिया गया है। ये आंकड़े दिखाते हैं कि हम बड़े लक्ष्य लेकर काम कर रहे हैं और जनता हमारे हर निर्णय, हर नीति, हर योजना के केंद्र में हैं।

कानून व्यवस्था को दुरुस्त रखना मेरी सरकार की प्राथमिकता है। आतंकवाद-मुक्त असम का हमारा संकल्प अटल है। 23 जनवरी, 2020 के दिन अल्फा, NDFB आदि 8 संगठनों के 644 सदस्यों ने आत्म-समर्पण किया है। हम सभी संगठनों को शांति अपनाने के लिए आमंत्रित करते हैं। स्थायी शांति, विकास के लिए परम आवश्यक है। पुलिस को प्रभावी और संवेदनशील बनाने के लिए हमने कई योजनाओं को हाथ

में लिया है। हमारी पुलिस और सक्षम बने, समर्थ हो, संवेदनशील हो, इसके लिए हम प्रयासरत हैं।

प्रशासनिक तंत्र को साफ-सुथरा बनाना मेरी सरकार की प्राथमिकता है। भ्रष्टाचार समाज को, व्यवस्था को दीमक की तरह चाट कर, खोखला बना रहा है। सार्वजनिक जीवन में शुचिता और पारदर्शिता की बहुत आवश्यकता है। इसलिए यह जरूरी है कि जो लोग बड़े पदों पर बैठें, उनकी चयन-प्रक्रिया साफ-सुथरी और पारदर्शी हो। असम लोक सेवा आयोग में और सुधार लाये जा रहे हैं। पहले जिस तरह से चयन-प्रक्रिया में धांधलियाँ हो रही थीं, उनका असर प्रशासनिक प्रणालियों पर पड़ा था। मेरी सरकार ने भ्रष्टाचार के खिलाफ कठोर कदम उठाते हुए, सरकारी नियुक्तियों में पूरी पारदर्शिता और ईमानदारी लाने का प्रयास किया है।

भाइयों एवं बहनों, हम राज्य में विकास को नयी दिशा और गति दे रहे हैं। देश की एक्ट ईस्ट पॉलिसी को सार्थक ढंग से लागू करने में असम की विशेष भूमिका है। मेरी सरकार इस दिशा में काम कर रही है। हम इस बात को मानते हैं कि व्यापार

और वाणिज्य के माध्यम से हम अपनी अर्थव्यवस्था को मज़बूत बना सकते हैं और दक्षिण पूर्व एशिया के प्रवेश द्वार के रूप में हमें हमारी पहचान बनानी होगी। संपर्क के सभी पहलुओं पर, जिनमें सांस्कृतिक, व्यावसायिक और वाणिज्यिक संपर्क शामिल हैं, काम करना होगा।

जहाँ उद्योग लगाने पर बल है, और उसके लिए आवश्यक नीतियों को लाया गया है, वहीं इस बात पर भी ध्यान दिया जा रहा है कि इन उद्योगों में रोज़गार पाने के लिए जिस कौशल की आवश्यकता होती है, उसे हमारे बच्चों में विकसित किया जाए। असम दक्षता विकास अभियान के माध्यम से इस वर्ष लगभग एक लाख बच्चों को दक्ष बनाने के लिए प्रशिक्षित किया गया है। भविष्य में जिन क्षेत्रों में रोज़गार की संभावनाएँ बनी रहेंगी, उनको ध्यान में रखकर हम दरंग जिले में अंतर्राष्ट्रीय स्तर का एक **दक्षता विश्वविद्यालय** स्थापित करने जा रहे हैं। लगभग 950 करोड़ की लागत से तैयार होने वाला यह विश्वविद्यालय जिसके चार कैंपस - ऊपरी असम, निचली असम, उत्तरी असम और बराक घाटी में होंगे,

भविष्योन्मुखी शिक्षा को ध्यान में रखते हुए हमारे युवाओं को कल के लिए तैयार करेगा। इस विश्वविद्यालय का काम तेजी से होगा। इसके लिए भारत सरकार ने ADB की मदद लेने की प्रक्रिया शुरू कर दी है और इस वर्ष के अंत तक इस परियोजना का काम शुरू हो जाएगा।

विकास तेज़ी से हो, इसके लिए पर्याप्त वित्तीय संसाधनों की आवश्यकता तो होगी ही। राज्य सरकार अपने राजस्व को बढ़ाने के हरसंभव प्रयास कर रही है। साफ नीयत के साथ शासन करने से विकास भी सही होगा, यह हमारा दृढ़ विश्वास है। पिछले वर्ष हमने राज्य के अपने संसाधनों में और वृद्धि की, जो प्रशासनिक तंत्र में आयी पारदर्शिता का नतीजा था। आबकारी, परिवहन और जीएसटी तथा अन्य प्रकार के राजस्व में रेकर्ड बढ़ोतरी दर्ज की गयी। इसके साथ ही, हम ढांचागत और सामाजिक विकास के लिए वर्ल्ड बैंक, ADB, AIB और NDB जैसी वित्तीय संस्थाओं से मदद लेने के लिए प्रयासरत हैं, जिससे हम विकास को और गति दे सकें। हमारा वित्तीय प्रबंधन बहुत प्रभावी है और हमने वैज्ञानिक ढंग से

बजट बनाना, संसाधन जुटाना, सही क्षेत्रों में आबंटन और खर्च को सुनिश्चित करना आदि को अपने वित्तीय प्रबंधन के केंद्र में रखा है। यही वजह है कि आज असम के विकास को गति मिली है, सही योजनाओं का चयन हो रहा है और उन योजनाओं के सफल क्रियान्वयन के लिए संसाधनों का अभाव नहीं रहा।

हम आज पूरे विश्वास के साथ कह सकते हैं कि आने वाला समय हमारा होगा। विश्व में भारत का विशिष्ट स्थान होगा, भारत में असम की अलग पहचान होगी। कुछ दिन पहले ही गुवाहाटी में राष्ट्रीय खेलो इंडिया का सफल आयोजन किया गया। देश के कोने-कोने से आये हमारे बच्चों ने खेल के मैदान में एक-दूसरे को चुनौती दी, पसीना बहाया, बाधाओं को पार किया और अपना सर्वश्रेष्ठ देने का प्रयास किया। असम की युवा प्रतिभाओं ने इन खेलों में शानदार प्रदर्शन किया। मैं उन सभी खिलाड़ियों को बधाई देता हूँ। यह समय है जब हम सभी असमवासी एकजुट होकर सभी चुनौतियों को झेलेंगे, बाधाओं को पार करेंगे और अपने राज्य के समग्र विकास के लिए पूरे

संकल्प के साथ पूरी निष्ठा के साथ, पूरे समर्पण के साथ अपने आपको झोंक देंगे। कल का सूरज हम अपने कंधों पर उठाकर लाएँगे, जिसका प्रकाश हर गहरी से गहरी कालिमा और घने से घने कुहासे को मिटा देगा।

जय हिंद

२०२०

असम सरकारी छापाखाना मे मुद्रित